दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

विहंगम दृश्य देखकर आगंतुक हुए गदगद...P-4

वर्ष : 17 अंक : 3 गाजियाबाद, मार्च, 2021 मूल्य : 4 रूपया पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

कोरोना लाइव

11,210,799	10,868,520	157,791	117,119,290
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

मतदाताओं की कुंडली फिर खंगालने पहुंचेगे बीएलओ

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों से निपटने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने एक बार फिर हकीकत खंगालने का निर्णय लिया है। इस कवायद में आगामी आठ मार्च से गांवों में फिर से बीएलओ को भेजा जाएगा। गांवों में पहुंचकर इस बार गहन पड़ताल होगी। इसके आधार पर मतदाताओं का नाम काटा और बढ़ाया जाएगा। पंचायत चुनाव के आरक्षण का निर्धारण होने के बाद यह सघन कवायद शुरू होगी। पंचायत के चुनाव को लेकर आरक्षण की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। पंचायत चुनाव की मतदाताओं में बोगस नाम से लेकर पलायित, दोहरे मतदाताओं के शामिल होने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि चुनाव कार्यालय के अनुसार जो शिकायतें मिली रही है। उन शिकायतों का निस्तारण शुरू करा दिया गया है। उधर आरक्षण जारी होने के बाद जिले के 161गांवों में से अधिकांश में मतदाता सूची की गड़बड़ी का मामला लगातार गर्म हो रहा है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा इसका समाधान तलाशा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ नाम फीडिग एवं प्रकाशन के बीच छूट गए हैं। तकनीकी स्तर पर हुई इस खामी को भी सुधारा जा रहा है। ऐसे में मतदाता घबनाएं नहीं। हालांकि बीएलओ के स्तर पर भी व्यापक गड़बड़ी की गई है।

दशकों पहले विवाहित होकर ससुराल गई बेटियों का नाम सूची में शामिल है, वहीं नए मतदाताओं का नाम गायब है। ऐसे में एक स्थान पर बैठकर व्यक्ति विशेष की जानकारी के अनुसार मतदाता सूची बनाने के संकेत मिलने लगे हैं। अधिकारी इस खामी को भी सुधारने में फिर से बीएलओ को गांवों में भेजेंगे। इसके बावजूद गड़बड़ी सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार कार्रवाई तय की जाएगी। अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार वैश्य के मुताबिक मतदाता नामावली की खामियों को ठीक किया जा रहा है। मताधिकार का प्रयोग करने से कोई वंचित नहीं होने पाएगा।

ग्राम पंचायत का आरक्षण घोषित होते ही चाय नाश्ता हुआ बंद

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। त्रिपक्षीय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आरक्षण आने से पहले लोग अपना अपना गणित फिट कर रहे थे। तो वही आरक्षण से गणित गड़बड़ आने पर ऐसे प्रत्याशियों ने अपने वोटरों को चाय नाश्ते से भी दूर कर दिया, यानी कि सुबह शाम घर पर लगी चौपाल भी अब खत्म हो गई और चाय नाश्ता भी वोटरों का खत्म और प्रत्याशियों के चेहरे लटके हुए देखे गए। जानकारी के अनुसार बता दें कि शासन स्तर से बने आरक्षण को लेकर जहां एक तरफ ग्राम पंचायत प्रधान पद एवं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 5 साल से लगातार मेहनत कर अपने घर के बाहर मेला लगाकर वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से चाय नाश्ते का लुत्फ उठा रहे वोटरो की दुकान हुई बंद। वही जैसे ही आरक्षण घोषित हुआ और आरक्षण में अपनी दाल गलती नहीं देखने पर ऐसे प्रत्याशियों ने चाय नाश्ते से भी तौबा कर ली, यानी कि घर के दरवाजे भी उन लोगों के लिए बंद हो गए जिन्हें सुबह शाम कम से कम चाय नाश्ते आराम से मिल जाया करते थे। सूत्रों की माने तो ऐसे प्रत्याशियों ने लोगो को चाय नाश्ते कराने से तोबा कर उन्हें हाथ जोड़कर विनती करते हुए देखे गए। इस दौरान अब उनका चुनाव लड़ना गड़बड़ा गया है। क्योंकि जहां एक तरफ आरक्षण ने प्रत्याशियों के गणित को गड़बड़ा दिया यानी कि उनकी 5

- आरक्षण में शासन द्वारा प्रतिशत के आधार पर घोषित होने पर प्रत्याशियों के चेहरे लटके

साल की मेहनत पर पानी फिर गया और चाय नाश्ते की दुकानें भी अब बंद हो गई, जो कल तक प्रत्याशियों के दरवाजे पर सुबह शाम नाश्ता कर उन्हें ही आने वाला प्रधान या जिला पंचायत सदस्य कहते कहते नहीं थकते थे। आज कह रहे हैं कि बड़ा लालची किस्म का इंसान है। जिसने आरक्षण घोषित होने के बाद ऐसा मानो जैसे कोई सांप सूंघ गया और चाय नाश्ते की दुकानें भी बंद बंद हो गई और घर पर लगे मेले को भी बंद कर दिया, यानी कि ऐसे लोगों के घर में अब मातम का सा माहौल बन गया, जो कल तक अपने आप को प्रधान और जिला पंचायत सदस्य लोगों से कहलवा कर गर्व महसूस कर रहे थे। शासन द्वारा त्रिपक्षीय चुनाव को लेकर आरक्षण घोषित होने के बाद बड़ा ही दिलचस्प चुनाव अब देखने को मिलेगा। हालांकि अभी कुछ प्रत्याशियों द्वारा बताया जा रहा है कि वह जिला प्रशासन और शासन को आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि उनकी बंद दुकान जल्द ही खुल जाए। फिलहाल ऐसे आसार कम दिखाई दे रहे हैं।

होली का त्यौहार व पंचायत चुनाव करीब आते ही शराब माफिया हुए सक्रिय

गाजियाबाद। होली का त्योहार व पंचायत चुनाव करीब आते ही शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। अवैध तश्करी की शराब व जहरीली शराब से पश्चिम उप्र के कई जनपदो में हुई मौत ने साबित किया कि अवैध शराब कारोबारी सक्रिय हैं। इसे रोकने में आबकारी विभाग व पुलिस फेल है। जिले में भी शराब की दुकानों पर नकली शराब बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। इस लेकर आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के शौकीन दुकानों से शराब लेते समय क्यूआर कोड को अवश्य देखें। इससे शराब असली है या नकली इसका पता चल जाएगा।

दुकानों पर गैर प्रांत की शराब रखना नहीं होगा आसान

शराब की अंग्रेजी, देशी, बियर व मॉडल शॉप की दुकानों पर गैर प्रांत की शराब की बोतल रखकर बेचना आसान नहीं होगा। क्यूआर कोड से पता चलेगा कि शराब यूपी में ड्यूटी पेड है या नहीं। शराब मिलने पर विभाग द्वारा उस दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व चोरी पर रोक लगेगी।

कूड़ा निस्तारण के नाम पर जबरदस्त गोलमाल

सीबीआई अकादमी के निकट बनाया नया डंपिंग ग्राउंड

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान केंद्र सरकार की टीम के दौरे के दौरान शहर की मुख्य सडकें साफ सुथरी दिखाई दे, इसके नाम पर क्या कुछ खेल हो रहा है,दूर तक भी ये देखने वाला कोई नहीं है। सूत्र बताते है कि कूडा निस्तारण के नाम पर जबरदस्त तरीके से खेल चल रहा है। यूं तो मेरठ रोड पर शाहपुर मोरटा के आस-पास किसानों की जमीनें किराए पर हासिल की गई है, हर माह बदले में एक मोटी रकम का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कुछ साफ निरीक्षक मनचाहे स्थानों पर कूडे का निस्तारण करा रहे है। कमला नेहरू नगर में सीबीआई अकादमी के निकट कूडे के ढेर में भयंकर आग लगने पर दमकल विभाग का सहारा लेना पडा। बताते है कि यही खेल विजय नगर जोन में भी चल रहा है,ताकि डीजल के नाम पर पैसे को हडपा जा सकें। जबकि हाल में कविनगर जोन के सफाई इंस्पेक्टर का डीजल के खेल से जुडा आडियों भी सामने आया था। सिदार्थ विहार में कूडा डंपिंग किए जाने पर प्रतिबंध के बाद मेरठ रोड पर शाहपुर मोरटा के निकट यू तो निगम के द्वारा किसानों की जमीनें डंपिंग ग्राउंड के लिए किराए पर हासिल की है। हर माह किसानों को एक मोटी रकम का भुगतान किया जा रहा है। बताते है कि निगम के स्वास्थ्य

- कूड़े के ढेर में आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाया
- सफाई इंस्पेक्टर अपने से बना रहे हैं डंपिंग यार्ड

विभाग के इंस्पेक्टर डीजल का पैसा डकारने के लिए नित्य नए खेल को कर रहे है। इसी कडी में कविनगर जोन के कूडे को कमला नेहरू नगर में सीबीआई अकादमी के निकट निस्तारित किया जा रहा था। बताते है कि किसी के द्वारा इस कूढे के ढेर को आग के हवाले कर दिया गया। आग के भयंकर रूप धारण करने पर किसी स्टाफ के द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई, बाद में दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सूत्र बताते है कि इसी तरह से लाइनपार में कांशी राम योजना के अंतर्गत बने भवनों के निकट भी कूडे का निस्तारण किया जा रहा है। सूत्र बताते है कि पूरा खेल केंद्र सरकार की टीम की आंखों में धूल झौंकने के लिए हो रहा है, ताकि कुछ इलाके उसे साफ सुथरे दिखाते हुए तमंगा हासिल किया जा सकें।

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING – U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
				MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11485.83	11517.45	*

निगम बांड के जरिये जुटाए जाएंगे 150 करोड़

औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में होगी पानी की आपूर्ति, रुकेगा भूजल दोहन

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। नगर निगम ने बजट के जरिये ना सिर्फ आम शहरी को खुश किया है बल्कि पर्यावरण की चिंता करने वालों को भी खुश होने का मौका दिया है। निगम ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पर्यावरण पर फोकस करते हुए प्रदूषण रोकने और भू-जल स्तर सुधारने को लेकर कई योजना तैयार की गई है। हरियाली बढ़ाने, तालाबों की खुदाई के अलावा भू-जल दोहन रोकने को लेकर भी निगम काम करेगा। यही वजह है कि नगर निगम के वित्त बजट को गाजियाबाद का ग्रीन बजट कहा जा रहा है। बजट में पर्यावरण के साथ-साथ औद्योगिक विकास और उद्यमियों की भी चिंता की गई है। नगर निगम ने औद्योगिक इकाईयों तक पाइपलाइन के जरिये पानी पहुंचाने की योजनों को बजट में स्वीकृति दी है। इससे औद्योगिक इकाईयों के गाजियाबाद से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम ने स्वावलंबी बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। नगर निगम जल्द ही म्युनिसिपल बांड जारी करेगा। बांड से मिले फंड का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में होगा। इसके साथ ही नगर निगम का फाइनैंसियल मैनेजमेंट भी पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। कार्यकारिणी बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव नगर निगम 150 करोड़ रुपए का म्युनिसपल बॉन्ड मार्च अंत तक जारी करने पर मुहर लग गई। एकाउंट ऑफिसर अरूण कुमार मिश्रा ने 1195 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया। जिसे कुछ संशोधन के साथ कार्यकारिणी ने पास कर दिया। बजट में 816 करोड़ रुपये की आय और 829 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। कार्यकारिणी ने यूजर चार्ज और हाउस टैक्स को लेकर शहर वासियों को राहत देने प्रस्ताव को भी पास कर दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि नगर निगम 150 करोड़ का म्युनिसपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में काम कर रहा है।

बिल्डरों में नहीं है किसी तरह का दूर तक भी खौफ

सीलिंग की कार्रवाई को बिल्डर दिखा रहे ठेंगा

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए यू तो अवैध निर्माण का मामला सामने आने पर बिल्डिंग को सील करने के दावे करता है, लेकिन देखा जाए तो जीडीए की सीलिंग कार्रवाई का दूर तक भी खौफ नहीं रह गया है। सीलिंग की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए जिन भूखंड पर एकल यूनिट के अंतर्गत 4 फ्लैट अथवा तीन फ्लैट बनने चाहिए उसके स्थान पर 15 से 25 फ्लैट बना रहे है। चार मंजिल के साथ छह-छह मंजिला बिल्डिंग का धडल्ले से निर्माण हो रहा है। पार्किंग के हिस्से को व्यवसायिक गतिविधि में तब्दील किया जा रहा है। बताते है कि पिछले छह माह के दौरान जिन बिल्डिंग को सील किया गया, यदि उनकी औचक तरीके से पडताल होती है तो निश्चित तौर से सील का दूर तक नामोनिशान मिलने वाला नहीं है। यहां बता दे कि जीडीए के संयुक्त सचिव सीपी त्रिपाठी कार्यालय से जारी ब्यान के माध्यम से कहा गया कि प्रवर्तन जोन 7 के अंतर्गत आने वाले वृदावन गार्डन के भूखंड संख्या 108, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन दो के भूखंड संख्या बी 119, राजेंद्र नगर सेक्टर पांच के भूखंड संख्या5/38, राजेंद्र नगर सेक्टर दो के भूखंड संख्या 3/10, 3/33 एवं राधे श्याम पार्क के भूखंड संख्या 60 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थीं, बिल्डरों के द्वारा सीलिंग से छेडछाड करते हुए लीक से हटकर फलैट के निर्माण पर पुनः सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बताते हैं कि जिन भूखंडों पर पुनः सीलिंग के दावे किए जा रहे है, देखा जाए तो मौके पर मौजूदा में भी निर्माण धडल्ले से किया जा रहा है। वह भी जीडीए के स्टाफ की मिलीभगत से। सूत्र बताते है कि लाकडाउन से पूर्व प्रवर्तन जोन 7 के अंतर्गत 40 से ज्यादा बिल्डिंग सील की गई थीं, उन तमाम बिल्डिंग की मौजूदा में क्या स्थिति है, ये दूर तक भी देखने वाला नहीं है। बताते है कि ये स्थिति केवल प्रवर्तन जोन 7 तक ही सीमित नहीं है। प्रवर्तन जोन छह आदि के अंतर्गत जिन भी बिल्डिंग को पिछले एक साल के दौरान सील किया गया, यदि उनकी वास्तविक स्थिति की पडताल होती है तो निश्चित तौर से स्थिति का खुलासा होना तय है। सूत्र बताते है कि सीलिंग की कार्रवाई के साथ निगरानी के थाना पुलिस को भेजे जाने वाले लेटर के बाद थाना पुलिस की भी जबरदस्त तरीक से चांदी कटती है। बताते है कि जहां तक अवैध निर्माण की स्थिति का सवाल है कि जीडीए के जिस कार्यालय में तमाम आला अधिकारी बैठते है। जीडीए कार्यालय के आस-पास जो मकान रहने के लिए आवंटित किए गए, अधिकांश का स्वरूप बदल दिया गया है। कुछ मकानों में रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे है। ऐसे में प्राधिकरण सीमा के दूसरे हिस्से में क्या स्थिति होगी खुद से अंदाजा लगाया जा सकता है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

सम्पादकीय

राहत के रास्ते

सत्येन्द्र सिंह

बाजार में अमूमन हर वस्तु की कीमतें बढ़ने का असर अब आम लोगों के उपभोग पर साफ दिखने लगा है। लेकिन महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसी रफ्तार से इजाफा किया जाता रहा तो आखिर लोगों के पास अपने जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या विकल्प बचेंगे! सही है कि पेट्रोल का इस्तेमाल आमतौर पर वे लोग करते हैं, जिनके पास वाहन हैं। लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी के हर मौके पर पेट्रोल के साथ–साथ डीजल के दाम भी बढ़ाए जाते हैं। यह अब एक सामान्य जानकारी है कि बाजार में आम उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति डीजलचालित वाहनों पर निर्भर है और डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही माल ढुलाई पर ज्यादा खर्च आता है और इसका सीधा असर थोक और खुदरा बाजार पर पड़ता है। इस तरह बाजार में अगर महंगाई की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम भी हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल का भाव जहां कई राज्यों में सौ रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, वहीं डीजल करीब अस्सी रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।

अब एसबीआइ के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो देश भर में पेट्रोल के भाव पचहत्तर रुपए और डीजल के भाव अड़सठ रुपए प्रति लीटर तक नीचे लाए जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र और राज्यों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाने से हिचक रही हैं। लेकिन अगर सरकार इस ओर कदम बढ़ाती है तो इसका कोई बड़ा आर्थिक असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहलकदमी से केंद्र और राज्यों के राजस्व में जीडीपी के महज 0.4 फीसदी के बराबर की कमी आएगी। फिर केंद्र और राज्यों में कई तरह के कर और उप–कर जुड़ जाने से भी स्थिति जटिल होती है। सवाल है कि अगर सरकार देश में महंगाई की वजह से लोगों की परेशानी को लेकर फिक्रमंद है, तो इस साधारण बोझ को सह कर वह पेट्रोल–डीजल की कीमतों में कमी लाने के उपाय क्यों नहीं कर सकती है!

विचित्र यह है कि पेट्रोल–डीजल की कीमतों को लेकर जब हालात चिंताजनक होने लगते हैं तो सरकार दलील देती है कि बाजार में यह उतार–चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर निर्भर है। हालांकि दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों के भाव तय करने के लिए किसी देश में पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। शायद ही कभी ऐसा हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल पाया। यह छिपी बात नहीं है कि क्रयशक्ति कम होने के चलते बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं के दाम के आसमान छूने की स्थिति में लोग अपने उपभोग का स्तर कम कर देते हैं।

जाहिर है, इससे अर्थव्यवस्था की गति भी प्रभावित होती है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को पहले भी इस तर्क पर जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जाती रही है कि अगर देश में एक कानून को समान स्तर पर लागू करने की दुहाई दी जाती है तो तेल को इससे बाहर क्यों रखा गया है। लेकिन राजस्व में कमी की आशंका के चलते पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पर अब तक गौर नहीं किया गया। अब एसबीआइ की ताजा रिपोर्ट के बाद उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

कोरोना की मार दुनिया के अधिकतर देशों के शिक्षा बजट पर पड़ी है

कोरोना की मार का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारों ने शिक्षा के बजट में कटौती की है। खासतौर से शिक्षा बजट में कमी निम्न व निम्न मध्यम आय वाले देशों ने की है तो उच्च व मध्यम उच्च आय वाले देशों में से कई देश भी शिक्षा बजट में कटौती करने में पीछे नहीं रहे हैं। रिपोर्ट में 65 प्रतिशत देशों द्वारा महामारी के बाद शिक्षा के बजट में कमी की बात की गई है। संभव है इसमें अतिश्योक्ति हो पर यह साफ है कि कोरोना महामारी का असर शिक्षा के क्षेत्र में साफ रूप से दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो कोरोना के कारण सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जहां एक ओर आज भी सब कुछ थमा–थमा–सा लग रहा हैं वहीं कोरोना की दूसरी लहर और अधिक चिंता का कारण बनती जा रही है।

वैक्सीन आने के बाद यह समझा जा रहा था कि अब कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा पर कोरोना की लगभग एक साल की यात्रा के बाद स्थिति में वापस बदलाव आने लगा है और जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसों में कमी आने लगी थी उस पर विराम लगने के साथ ही नए केस आने लगे हैं।

कोरोना वैक्सीन आने के बाद यह समझा जा रहा था कि अब कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा पर कोरोना की लगभग एक साल की यात्रा के बाद स्थिति में वापस बदलाव आने लगा है और जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसों में कमी आने लगी थी उस पर विराम लगने के साथ ही नए केस आने लगे हैं। हालांकि समग्र प्रयासों से दुनिया के देशों में उद्योग धंधे पटरी पर आने लगे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार भी दिखाई देने लगा है पर अभी भी कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो कोरोना के कारण अधिक ही प्रभावित हो रही हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था प्रमुख है। भारत सहित कई देशों में स्कुल खुलने लगे हैं तो उनमें बड़ी कक्षा के बच्चों ने आना भी शुरू किया है पर अभी तक पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के पटरी पर आने का काम दूर की कौड़ी दिख रही है।

लगभग एक साल से शिक्षा व्यवस्था ठप्प–सी हो गई है। प्राइमरी से उच्च शिक्षा व्यवस्था तक को पटरी पर लाना सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि कोरोना के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के भले ही कितने ही दावे किए गए हों पर उन्हें किसी भी स्थिति में कारगर नहीं माना जा सकता। इसका एक बड़ा कारण दुनिया के अधिकांश देशों में सभी नागरिकों के पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नहीं है। इंटरनेट सुविधा और फिर इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता लगभग नहीं के बराबर है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज खोलना किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना प्रोटोकाल की पालना अपने आप में चुनौती है, ऐसे में आवश्यकता तो शिक्षा बजट को बढ़ाने की है पर उसके स्थान पर शिक्षा बजट में कटौती शिक्षा के क्षेत्र में देश दुनिया को पीछे ले जाना ही है। आवश्यकता तो यह थी कि कोरोना प्रोटोकाल की पालना सुनिश्चित कराने पर जोर देते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोलने की बात की जाती। इसके लिए कक्षाओं में एक सीमा से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ना होने, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सैनेटाइजरों की उपलब्धता और अन्य सावधानियां सुनिश्चित करने की व्यवस्था अतिरिक्त बजट देकर की जानी चाहिए थी।

इसी तरह से अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाना चाहिए था क्योंकि ऑनलाइन क्लासों के कारण बच्चों में सुनाई देने में परेशानी जैसे साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की गुणवत्ता और उसके परिणाम भी अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। अपितु बच्चों में मोबाइल व लैपटॉप के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरोना के कारण येन–केन प्रकारेण बच्चों को प्रमोट करने के विकल्प से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी ही होगी। दुनिया के देशों की सरकारों को इस दिशा में गंभीर विचार करना ही होगा। गैरसरकारी संस्थाओं को भी इसके लिए आगे आना होगा क्योंकि यह भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है तो दूसरी और स्वास्थ्य मानकों की पालना भी जरूरी हो जाता है।

केवल और केवल फीस लेने या नहीं लेने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निम्न व निम्न मध्यम आय वाले देशों या यों कहें कि अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील देश ही नहीं अपितु विकसित देशों के सामने भी कोरोना नई चुनौती लेकर आया है। सभी देशों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। परिजनों की अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। आधारभूत सुविधाएं व संसाधन होने के बावजूद विकसित देशों में भी शिक्षा को पटरी पर नहीं लाया जा सका है। कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार मास्क, सैनेटाइजर, थर्मल स्केनिंग और दूरी वाली ऐसी स्थितियां हैं जिसके लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकता है। यह सभी आधारभूत व्यवस्थाएं व संसाधन उपलब्ध कराना मुश्किल भरा काम है तो दूसरी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा यह अपने संसाधनों से जुटाना आसान नहीं है। अभिभावकों से इसी राशि को वसूलना भी कोरोना महामारी से टूटे हुए लोगों पर अतिरिक्त दबाव बनाने के समान ही होगा। आम आदमी वैसे ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। नौकरियों के अवसर कम हुए हैं तो वेतन कटौती का दंश भुगत चुके हैं। अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा को बचाना बड़ा दायित्व हो जाता है। इसके लिए दुनिया के देशों की सरकारों को कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं करनी ही होंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसके लिए आगे आना होगा। शिक्षा को बचाना हमारा सबका दायित्व हो जाता है।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@gmail.com गाजियाबाद, मार्च, 2021

विहंगम दृश्य देखकर आगंतुक हुए गदगद

लैंडक्रॉफ्ट द्वारा आयोजित फ्लॉवर शो बना आकर्षण का केन्द्र

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। लेडक्राफ्ट और हॉर्टिकल्चर फ्लोरीकल्चर सोसायटी ऑफ गाजियाबाद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फ्लोवर शो एवं चटकारे फेस्टिवल का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। जिसमें दिल को कैसे सेहतमंद रखें इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। फ्लॉवर शो में सबसे अधिक फोकस आक्सीजन देने वाले पौधे और ऑर्गेनिक पौधों पर रखा गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खानपान और सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई। इस बार के फ्लॉवर शो का मुख्य आकर्षण है बोनसाई के पेड, पुष्प कला इस बार की थीम को भी फूलों से हृदय और डोल्फिन मछली, हाथी, घोडे भी बनाए गए हैं। जिसकी सभी लोगों ने काफी पसंद किया। पहले दिन सभी ने स्टॉल लगाया। जिसमें अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे इम्यूनिटी बूस्टर पौधे, सहित विभिन्न विदेशी पौधे और कैक्टस की विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल है। इस शो में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम, नोएडा प्राधिकरण, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग एवं डेटल कॉलेज, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, शम्भु दयाल कॉलेज के प्रतिभागियों ने भाग लिया। फलोरीकल्चर सोसायटी की अध्यक्षा रमा त्यागी ने बताया कि पहले दिन जजों के पैनल ने बैस्ट स्टाल और प्रदर्शनी आदि को चयन किया। जिनको अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शो की थीम के अनुसार लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि घरों में या अपने गार्डन में ऑक्सीजन देने वाले पौध ज्यादा लगाएं जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, नीम आदि। फ्लोवर शो में शाम को काफी लोगों की भीड़ जुटी। जिन्होंने फ्लावर शो के साथ-साथ विभिन्न स्टालों पर खानपान का आनंद लिया। लैंडक्राफ्ट के निदेशक ललित जायसवाल ने बताया कि यह शो सात मार्च तक गोल्फ लिंक्स में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा।

मांगे पूरी न होने पर विद्युत मजदूर संगठन ने जाहिर की नाराजगी

गाजियाबाद। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर सभा की जिला इकाई ने नियमित और संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की है। दोनों संगठनों के बैनर तले धरना दिया गया। इस दौरान लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. लखनऊ के अध्यक्ष को इस संबंध में ज्ञापन भी भेजा गया है। धरनास्थल पर वक्ताओं ने कहा कि नियमित और संविदा कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी हो रही है। इससे कर्मियों में आक्रोश बढ़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कार्यालय सहायक एवं टीजी- 2 तथा समकक्ष को नियुक्ति ग्रेड पे 4200 और तृतीय टाईम स्केल ग्रेड पे 6600 रुपए देने, पुरानी पेंशन लागू करने, लिपिकीय संवर्गो के रिक्त पदों पर पदोन्नति, कार्यालय सहायकों को एडहाक नियुक्ति की तिथि से पदोन्नति, जल विद्युत कर्मियों के साथ भेदभाव समाप्त करने, संविदा कर्मियों को ईएसआई की सुविधा देने, मृतक संविदा कर्मियों के परिवार को अनुग्रह धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने, 5 साल से अधिक समय से कार्यरत एवं पोर्टल पर अंकित संविदा कर्मियों को विभाग में रिक्त 35 हजार पदों के विरूद्ध समायोजित करने आदि मांग की गई।

म्युनिसिपल परफॉर्मेंस, सर्विस कैटेगरी में भारत में गाजियाबाद प्रथम स्थान पर

गाजियाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गाजियाबाद को सेवा प्रदाता श्रेणी मे प्रथम स्थान दिया गया। नगर निगम शहर को पानी सफाई सीवर उद्यान निर्माण व अन्य बहुत सी सेवाएं सर्विस मुहैया कराता है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के कुशल नेतृत्व में शहर के निवासियों को नगर निगम से संबंधित सभी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं सभी विभाग जलकल निर्माण प्रकाश उद्यान सफाई व अन्य विभागों द्वारा जनता के लिए सेवाएं दी जाती हैं जिस हेतु गाजियाबाद को भारत सरकार द्वारा भारत में प्रथम स्थान दिया गया है जिसका स्कोर 73.92 प्राप्त हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम को महापौर आशा शर्मा, पार्षदों, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों, द्वारा बधाई दी गई।

0समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कानून, 1956 आठवें नियम के अन्तर्गत अपेक्षित "उद्योग विहार" नामक समाचार पत्र से सम्बंधित स्वाममत्व और अन्य बातों का ब्यौरा :

प्रपत्र –4

1. प्रकाशन स्थान	:	"उद्योग विहार" बी ई 243 जी. एफ., अवंतिका, गाजियाबाद
2. प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	सत्येन्द्र सिंह
क्या भारत के नागरिक हैं	:	हाँ
4. प्रकाशक का नाम	:	सत्येन्द्र सिंह
5. संपादक का नाम	:	सत्येन्द्र सिंह (दिल्ली एन सी आर)
क्या भारत के नागरिक हैं	:	हाँ
पता	:	बी ई 243 जी एफ, अवंतिका, गाजियाबाद
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों, तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	लीगल इन्फोसोलुसंस प्राइवेट लिमिटेड बी ई 243 जी एफ, गाजियाबाद

मैं **सत्येन्द्र सिंह** एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

हस्ताक्षर
सत्येन्द्र सिंह,
(मुद्रक व प्रकाशक)

पुलिस लाइन में आयोजित हुआ रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह

एसएसपी ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी

-उद्योग विहार (मार्च 2021)-

गाजियाबाद। हरसांव स्थित पुलिस लाइन्स गाजियाबाद के परेड ग्राउण्ड में आरक्षी नागरिक पुलिस का दीक्षान्त समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। दीक्षान्त समारोह परेड में विभिन्न जनपदों से आधार भूत प्रशिक्षण के लिए 122 रिक्रूट आरक्षियों ने हिस्सा लिया। जिसमें अलीगढ से 24, हाथरस-38, जालौन-1, कानपुर नगर-8, सहारनपुर-2, मुजफ्फरनगर-1, मेरठ-1, बागपत-1, मैनपुरी से 9 तथा जनपद इटावा से 26 कुल-111 रिक्रूट आरक्षियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। जिनका प्रशिक्षण 28 अगस्त 2020 से प्रारम्भ हुआ था। 1 रिक्रूट आरक्षी का सहायक अध्यापक पद पर चयन होने तथा 01 रिक्रूट आरक्षी लगातार अनुपस्थित होने के फलस्वरूप 109 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा इस दीक्षान्त परेड में

- **परेड में 47वीं वाहिनी पीएसी की बैण्ड यूनिट की धुन पर मार्च पास्ट किया**
- **सभी रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करायी**

प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। दीक्षान्त परेड के परेड कमाण्डर प्रथम रिक्रूट आरक्षी 3 विनय कुमार, परेड कमाण्डर द्वितीय रिक्रूट आरक्षी 2 रोबिन कुमार तथा परेड कमाण्डर तृतीय रिकूट आरक्षी 108 अनमोल सिंह नियुक्त थे। परेड में 47वीं वाहिनी पीएसी की बैण्ड यूनिट की धुन पर मार्च पास्ट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा परेड के निरीक्षण के उपरान्त परेड को सम्बोधित किया तथा प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगणों एवं प्रशिक्षण स्टाफ को बधाई दी। सभी रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करायी। दीक्षान्त परेड समारोह की सम्पूर्ण व्यवस्था ऊदल सिंह, प्रतिसार निरीक्षक, गाजियाबाद के निकट पर्यवेक्षण में की गयी।

इस अवसर पर डा0 ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय, रामानन्द कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक यातायात, लाइन्स, समस्त क्षेत्राधिकारी गाजियाबाद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक रेडियो अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक "सत्येन्द्र सिंह" द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 मोबाइल नं. : 9818036460 / 9818697406 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com संस्थापक : शीतला प्रसाद सिंह प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह सम्पादक : बबिता सिंह सह सम्पादक : राजेश सिंह